

## बढ़ते संरक्षणवाद के बीच उभरते बाज़ार

यह एडिटरियल 15/09/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “[Strategies for emerging markets at a time when protectionism is rising](#)” पर आधारित है। इस लेख में बढ़ते संरक्षणवाद के संदर्भ में उभरते बाज़ारों के समक्ष आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है जो सतत एवं सुदृढ़ विकास को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक उपायों के महत्त्व को रेखांकित करता है।

परलिमिंस के लिये: [भारत का आत्मनिर्भर भारत](#), [यूरोपीयन युनियन कर्टिकिल रॉ मटेरियलस एक्ट](#), [यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र \(CBAM\)](#), [RCEP](#), [BRICS](#), [इन्डो-प्रशांत आर्थिक कार्यवाहिका \(IPEF\)](#)

मेन्स के लिये: वैश्वीकृत विश्व में बढ़ते संरक्षणवाद के कारण, बढ़ते संरक्षणवाद में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर बनाने वाले कारक, भारत-अमेरिका व्यापार विवाद

उभरते हुए बाज़ार आज एक नरिणायक मोड़ पर खड़े हैं, जसि पर बढ़ते [संरक्षणवाद](#) के वैश्विक पुनरुत्थान का गहरा प्रभाव है। जो अर्थव्यवस्थाएँ कभी [वसितृत व्यापार नेटवर्क](#) और [वदिशी नविश के नरितर प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण](#) की गति पर वकिसति हो रही थीं, वे अब ऐसी स्थिति में हैं जहाँ उन्हें नए अवसरों और गंभीर चुनौतियों, दोनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक अंतरमुखी (Inward-looking) रणनीतियों की ओर रुख कर रहे हैं।

### वैश्वीकृत विश्व में संरक्षणवाद क्यों बढ़ रहा है?

- **आर्थिक राष्ट्रवाद और वओदयोगीकरण:** वनरिमाण क्षेतर में नौकरियों के नुकसान से जूझ रहे देश पुनरस्थापन को प्राथमकिता दे रहे हैं।
  - यू.एस. [इन्फ्लेशन रडिक्शन एक्ट अधिनियम, 2022](#) घरेलू स्वच्छ ऊर्जा वनरिमाण को प्रोत्साहित करता है, जबक्युरोपीयन युनियन [कर्टिकिल रॉ मटेरियलस एक्ट](#) आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने और आयात पर नरिभरता कम करने का प्रयास करता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतदिवंदवता और रणनीतिक अलगाव:** अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण [ह्यूवई \(Huawei\)](#) जैसी कंपनियों पर प्रतबिंध एवं उन्नत अर्द्धचालक प्रोद्योगिकी पर नरियात नयितरण लागू हो गए हैं।
  - इसी प्रकार, भारत की [आत्मनिर्भर भारत पहल](#) महत्त्वपूर्ण आयातों पर नरिभरता कम करने के प्रयासों को दर्शाती है।
- **कोवडि-19 के बाद आपूर्ति शृंखला की कमजोरियाँ:** महामारी ने [फार्मास्यूटिकल्स](#), [इलेक्ट्रॉनिक्स](#) और [चकितिसा](#) आपूर्ति की नाजुक आपूर्ति शृंखलाओं को उजागर किया।
  - [स्टील और सौर पैनलों के उत्पादन पर चीन के नयितरण](#) के कारण अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं भारत ने घरेलू उद्योगों को सब्सिडी वाले आयातों से बचाने के उद्देश्य से टैरफि लगाए हैं।
  - इसके जवाब में, जापान की आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता रणनीति चीन से दूर वविधीकरण को बढ़ावा देती है, जबकअमेरिकी [चपिस अधिनियम](#) घरेलू [सेमीकंडक्टर उत्पादन](#) को बढ़ावा देता है।
- **बढ़ती असमानता और जनवाद:** बरेक्जटि यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण के वरिद्ध जनवादी प्रतकिरिया कसि प्रकार उभरी, जसिका मुख्य कारण आर्थिक असमानता एवं स्थानीय उद्योगों की रक्षा की माँग रही।
  - अमेरिका में, [स्टील और एल्युमीनियम](#) पर टैरफि को घरेलू नौकरियों की सुरक्षा के रूप में उचित ठहराया गया था, जो चुनावी दबावों को दर्शाता है।
  - [ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देश कृषि क्षेत्रों की रक्षा के लिये व्यापार अवरोध](#) लगाते हैं, जो खुलेपन के वैश्विक आह्वान के बावजूद व्यापार वारता में संप्रभुता का संकेत देते हैं।
- **पर्यावरण और जलवायु संबंधी चिंताएँ:** [यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र \(CBAM\)](#) उच्च-कार्बन आयातों पर टैरफि लगाता है, जसिसे नरियातकों को सख्त पर्यावरणीय मानकों को अपनाने के लिये वविश होना पड़ता है।

### बढ़ते संरक्षणवाद के बीच उभरती अर्थव्यवस्थाओं को क्या कमजोर बनाता है?

- **उच्च व्यापार नरिभरता:** वयितनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EM) की वृद्धि मुख्यतः नरियात पर आधारित है। ऐसे में शुल्क और गैर-शुल्कीय बाधाएँ उनके लिये विशेष रूप से हानिकारक सिद्ध होती हैं।
  - अमेरिका ने भारतीय नरियात पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे व्यापार प्रवाह बाधित हुआ है और वस्त्र, दवा एवं इंजीनियरिंग घटक जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
  - **ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनशिएटिव (GTRI)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये शुल्क 60.2 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय नरियात को प्रभावित करेंगे, जिसमें वस्त्र, रतन-आभूषण, झींगा, कालीन एवं फरनीचर शामिल हैं।
  - जब तेल, तांबा या कृषि नरियात की वैश्विक माँग गिरती है, तो लैटिन अमेरिकी व अफ्रीकी उभरते बाजारों को नुकसान होता है।
- **व्यापार वचिलन और चीन शाक 2.0:** चीन पर अमेरिकी टैरिफ ने चीन को भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे अन्य उभरते बाजारों में अतिरिक्त नरियात को पुनर्निर्देशित करने के लिये प्रेरित किया है, जिससे घरेलू उद्योगों पर सस्ते आयातों से प्रतस्पर्द्धा करने का दबाव बढ़ रहा है।
- **तकनीकी व्यवधान:** स्वचालन और AI श्रम बाजार को बदल रहे हैं। भारत जैसे श्रम-समृद्ध देशों को बढ़ते पूंजी-श्रम अनुपात की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ब्लू-कॉलर एवं व्हाइट-कॉलर, दोनों क्षेत्रों में नौकरियों के वसिस्थापन का खतरा है।
  - **NASSCOM** की एक रिपोर्ट (2023) बताती है कि AI और स्वचालन वर्ष 2030 तक भारत में 69 मिलियन नौकरियों को खत्म कर सकते हैं, विशेषकर वनरिमाण एवं ग्राहक सेवा जैसे पुनरावृत्त वाले कार्यों वाले क्षेत्रों में।
- **आपूर्ति शृंखला की कमजोरी:** कोविड-19 व्यवधानों ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर नरिभरता को उजागर किया। चीनी API (एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट) पर नरिभर भारत का दवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ।
- **कमजोर घरेलू बाजार:** वकिसति अर्थव्यवस्थाओं के वपिरीत, उभरते बाजारों में प्रायः बाहरी झटकों को कम करने के लिये सुदृढ़ आंतरिक माँग का अभाव होता है।
  - उभरते बाजारों में बड़ी युवा आबादी को रोजगार सृजन और कौशल विकास की आवश्यकता है; इस पर ध्यान न देने से सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि दक्षिण एशिया में हाल ही में युवाओं के वरिध प्रदर्शनों में देखा गया है।

## भारत-अमेरिका व्यापार वविादों का भारत के उभरते बाजारों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **उच्च शुल्क लगाना:** अमेरिका ने भारतीय नरियात पर 25% शुल्क लगाया है और आगे 25% की और बढ़ोतरी तय की है। इससे कुछ भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50% हो जायेगा।
  - इससे नरियात लागत में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे भारतीय उत्पाद महत्त्वपूर्ण अमेरिकी बाजार में कम प्रतस्पर्द्धी हो जाते हैं, जहाँ वर्ष 2024 में लगभग 48.2 बिलियन डॉलर का नरियात हुआ था।
  - प्रमुख भारतीय नरियात क्षेत्र जैसे सी-फूड (झींगा), जैविक रसायन, कालीन, परधान, आभूषण और औद्योगिक वस्तुओं पर 50% से अधिक शुल्क दरें लागू हैं, जिससे राजस्व एवं बाजार हसिसेदारी पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
- **व्यापार वारता में गतरिध:** व्यापार वारता के कई दौर मुख्य रूप से अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिये बाजार अभिगम्यता और रूस से भारत के नरितर कच्चे तेल के आयात पर असहमति के कारण रुके हुए हैं।
- इससे अनश्चितता बढ़ती है और नरियात वृद्धि योजनाएँ बाधित होती हैं।
- **आर्थिक विकास का दबाव:** टैरिफ और चल रहे व्यापार तनाव भारतीय नरियातकों के लिये अनश्चितता बढ़ा रहे हैं, जिससे नरियात-उन्मुख उद्योगों की वृद्धि धीमी पड़ सकती है तथा नरियात आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़े रोजगार, MSME एवं किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है।
- **रणनीतिक और राजनीतिक परिणाम:** व्यापार वविाद ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे भविष्य के रणनीतिक सहयोग को लेकर अमेरिका में चर्चाएँ बढ़ गई हैं तथा नविशकों का वशिवास और व्यापारिक साझेदार प्रभावित हुए हैं।
  - यह तनाव रूस और पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंधों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को जटिल बना रहा है।

## वर्ष 2025 में बढ़ते अमेरिकी टैरिफ और व्यापार तनाव के प्रत्युत्तर में भारत ने क्या कदम उठाए हैं?

- **संयमति गैर-प्रतशिधी दृष्टिकोण:** भारत ने टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई न करने का वकिल्प चुना, बल्कि तात्कालिक हतियों की रक्षा करते हुए दीर्घकालिक आर्थिक संबंध बनाए रखने के लिये एक रणनीतिक और शांत रुख अपनाया।
- **घरेलू वनरिमाण को बढ़ावा देना:** आत्मनरिभर भारत के माध्यम से, सरकार ने अस्थिर बाह्य बाजारों पर नरिभरता कम करने के लिये घरेलू वनरिमाण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आत्मनरिभरता पहल को गति दी।
- **संरचनात्मक सुधार और GST सरलीकरण:** घरेलू खपत को बढ़ावा देने और बढ़ते टैरिफ के बीच नरियातकों को प्रतस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने में सहायता करने के लिये कई वस्तुओं पर GST में कटौती सहित सुधार लागू किये गए।
- **नरियात संवर्द्धन मशिन शुरु करना:** झींगा, परधान, आभूषण, हस्तशालिप और कालीन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लक्षित ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा टैरिफ के प्रभावों को कम करने के लिये ₹25,000 करोड़ का नरियात संवर्द्धन मशिन शुरु किया गया।
- **MSME और प्रमुख क्षेत्रों के लिये सहायता:** उच्च टैरिफ से प्रभावित MSME की सहायता के लिये वशिष वित्तीय उपाय जैसे कि संपारश्वकि-मुक्त ऋण, रियायती ब्याज दरें और नरियात बीमा शुरु किये गए।
- **व्यापार साझेदारी का वविधीकरण:** भारत ने वैश्विक बाजारों और BRICS जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को तेज किया, जिससे अमेरिकी बाजार पर नरिभरता कम हुई।
- **वित्तीय सहायता और ऋण समर्थन:** सरकार ने टैरिफ-संबंधी अनश्चितताओं के खिलाफ नरियात-उन्मुख क्षेत्रों को मजबूत करने के लिये कार्यशील पूंजी तक अभिगम्यता एवं नरियात ऋण की सुविधा प्रदान की।
- **उत्पाद-वशिषिट छूट और व्यापार वारता:** चल रही वारता में उद्योगों को असंगत टैरिफ भार से बचाने के लिये संवेदनशील उत्पादों पर छूट या टैरिफ में कमी की माँग की गई।

## भारत जैसे उभरते बाजारों को आगे बढ़ने के लिये कौन-से रणनीतिक कदम उठाने चाहिये?

- **व्यापार साझेदारों का वविधीकरण:** RCEP और **इदि-प्रशांत आर्थिक कार्यद्वैचा (IPEF)** जैसे कषेत्रीय व्यापार समझौतों की संभावना तलाशकर एकल बाज़ारों पर नरिभरता कम कयिा जाना चाहयि ।
- **घरेलू उद्योगों को मज़बूत करना:** मेक इन इंडयिा जैसी पहलों, अवसंरचना के वकिस और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को समर्थन देने वाली नीतयिों पर ध्यान केंद्रति कयिा जाना चाहयि ताक सिमुत्थानशीलता को बढ़ाया जा सके ।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार में नविश:** श्रम को असमान रूप से वसि्थापति कयि बनिा उत्पादकता बढ़ाने के लयि अनुसंधान एवं वकिस, डजिटिल साकषरता और AI एडॉप्शन को बढ़ावा दयिा जाना चाहयि ।
- **सामाजिक सुरक्षा संजाल:** कमज़ोर आबादी की सुरक्षा के लयि बेरोज़गारी लाभ, कल्याणकारी कार्यक्रम और पुनर्कौशल पहलों को लागू कयिा जाना चाहयि ।
- **सक्रयि बहुपकषीय जुड़ाव:** नयिम-आधारति व्यापार प्रणाली सुनशिचति करने, उभरते बाज़ारों के हतिों की रक्षा करने और वविदों को प्रभावी ढंग से हल करने के लयि वशि्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को मज़बूत कयिा जाना चाहयि ।

## नषिकरष:

भारत जैसे उभरते हुए बाज़ार आज एक नरिणायक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ उन्हें बढ़ते संरक्षणवाद और तेज़ी से बदलते तकनीकी परविरतन की दोहरी चुनौतयिों का सामना करना पड़ रहा है । अर्थशास्त्री दानी रॉडरिक के शब्दों में, “**प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात, आर्थिक विकास, और वैश्वीकरण**”

इसका संकेत है कि खंडति वैश्विक व्यवस्था में आगे बढ़ने के लयि भारत जैसे देशों को धारणीय और व्यावहारिक रणनीतयिों की आवश्यकता है ।

**प्रश्न.** “बढ़ता संरक्षणवाद भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लयि गंभीर चुनौतयिों प्रस्तुत करता है ।” इस संदर्भ में भारत के नरियात कषेत्र की कमज़ोरयिों पर चर्चा कीजयि और हाल की नीतगित प्रतिकरियिाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजयि ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

**प्रश्न 1.**

नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत में 1991 में आर्थिक नीतयिों के उदारीकरण के बाद घटति हुआ/हुए है/हैं ? (2017)

1. GDP में कृषिका अंश बृहत् रूप से बढ़ गया ।
2. वशि्व व्यापार में भारत के नरियात का अंश बढ़ गया ।
3. FDI का अंतर्वाह (इनफ्लो) बढ़ गया ।
4. भारत का वदिशी वनिमिय भण्डार बृहत् रूप से बढ़ गया ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

**प्रश्न 1.**

क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टिकीजयि । (2025)

